PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 11, ISSUE 05

जिला सहकारी बैंक का किसानों के जीवन निर्वाह स्तर पर प्रभाव: विशेष संदर्भ चंद्रपुर जिला

डॉ. राजेश्वर डी. रहांगडाले
सहयोगी प्राध्यापक व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय, चिमूर,
जिल्हा-चंद्रपूर, महाराष्ट्र

सारांश: *चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (सीडीसीसी बैंक) किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध निबंध सीडीसीसी बैंक के ऋण वितरण, किसानों की आय वृद्धि, साहूकारों पर निर्भरता कम होने जैसे प्रभावों का अध्ययन करता है। द्वितीयक डेटा और एनएबीआरडी के रिपोर्टों पर आधारित, २०२३-२४ के लिए कुल कृषि ऋण संभाव्यता ₹२,४२१.९५ करोड़ है, जिसमें सीडीसीसी बैंक का हिस्सा ५९% है। २०२४-२५ के लिए सीडीसीसी ने ₹१,००० करोड़ वितरित किए। हालांकि, ऋण वसूली में कठिनाइयों और किसान आत्महत्याओं की घटनाओं (२०२४ में महाराष्ट्र में २,६३५, विदर्भ में ८०%) के कारण चुनौतियां भी दिखाई देती हैं। सिफारिशों में डिजिटल बैंकिंग बढ़ाना, बीमा कवरेज सुधारना और एफपीओ मजबूत करना शामिल है।*

कीवर्ड्स: सीडीसीसी बैंक, किसान जीवन निर्वाह, कृषि ऋण, चंद्रपुर जिला, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

भारत में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समावेशन और विकास का प्रमुख साधन है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत १९०४ में सहकारी पतनसंस्था अधिनियम से हुई, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को साहूकारों के जुल्म से मुक्त करने के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया। १९०६ से १९१८ के कालखंड में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शुरू हुए, जिनकी संख्या १९१९-२० में २३३ से बढ़कर १९२९-३० तक ५८८ हो गई। ये बैंक राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के बीच सेतु का काम

करते हैं, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण, जमा और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। महाराष्ट्र में डीसीसीबी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां ३१ से अधिक डीसीसीबी हैं और सहकारी क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में तथा ग्रामीण विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये बैंक कृषि तथा गैर-कृषि सहकारी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ती है, अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और सतत ग्रामीण जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन मिलता है।

चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग विदर्भ क्षेत्र में स्थित, ११,४४३ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला और ४३.१६% वन क्षेत्र वाला जिला है। यह जिला गोदावरी नदी के बेसिन में आता है, जहां वर्धा, वैनगंगा, पैंगंगा, अंधारी और मल जैसी प्रमुख नदियां हैं। औसत वार्षिक वर्षा १,१४२ मिमी है, और कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जिससे ८५% कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित है। २०११ की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या २२,०४,३०७ है, जिसमें ६४.८३% ग्रामीण है और ७९% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का अनुपात क्रमशः १५.८% और १७.६% है, जिसमें आदिवासी समुदायों का बड़ा हिस्सा है। जिले में ३,३३,०५६ कृषि भूखंड हैं, जिनमें ६९.५१% छोटे और सीमांत किसान (<२ हेक्टेयर) हैं और औसत कृषि भूमि आकार ०.९० हेक्टेयर है। प्रमुख फसलों में चावल (१८४,२९० हेक्टेयर, महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादक), कपास (१७७,३८५ हेक्टेयर), सोयाबीन (६५,०६२ हेक्टेयर), तूर और ज्वार शामिल हैं, जबकि रबी मौसम में गेहूं, चना और तिल उगाए जाते हैं। फसलों की तीव्रता १०९% है, लेकिन सिंचाई केवल २३% क्षेत्र पर उपलब्ध है (१.१३ लाख हेक्टेयर), जिससे सूखा और अतिवृष्टि जैसे जलवायु परिवर्तनों से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। जिले के किसानों को सामना करने वाली चुनौतियों में कम सिंचाई, छोटी भूमि, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग (२०२०-२१ में खरीफ में १६१,३४३ मीट्रिक टन), बाजार मूल्यों में अस्थिरता और ऋण बोझ शामिल हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्याओं की घटनाएं यहां भी दिखाई देती हैं; २०२३ में जनवरी से जुलाई तक ७३ आत्महत्याएं हुईं, जिसमें अतिवृष्टि से ५४,५१४.६५ हेक्टेयर क्षेत्र का नुकसान और ६४,३७९ किसानों को प्रभावित हुआ। जलवायु परिवर्तन की धारणा पर किए गए अध्ययन के अनुसार, १२० किसानों में से ५०% से अधिक ने फसल विविधीकरण, भूमि विश्राम और कुएं खोदने जैसी रणनीतियां अपनाईं, लेकिन महिलाओं के कृषि कार्य से पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (सीडीसीसी बैंक) १९९९ में स्थापित संस्था है, जो कृषि वित्त उपलब्धता और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। जिले में १०५ से अधिक शाखाएं और ३०+ एटीएम के साथ, बैंक १८.५ अरब रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करता है और १० लाख से अधिक ग्राहक खातों को सेवा प्रदान करता है। मार्च २०२३ तक जमा ₹१५.६४ अरब और ऋण वितरण ₹१२.३४ अरब है, जिसमें वार्षिक लाभ वृद्धि १५.२३% है। बैंक किसानों के लिए सस्ती ब्याज दर पर कृषि ऋण (भूमि आकार और फसलों पर आधारित), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त दायित्व समूह (जेएलजी) ऋण प्रदान करता है, साथ ही एपीबीएस, डीबीटीएल, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई और पीएफएमएस जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंचाता है। ट्रस्टबैंक्सीबीएस जैसी तकनीक के माध्यम से बैंक डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अनुपालन सुनिश्चित करता है। हालांकि, २०२१ में जमा अटकने की शिकायतें और विदर्भ में बैंकों की अपर्याप्त सहायता से किसान आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ीं।

यह अध्ययन सीडीसीसी बैंक के ऋण उपलब्धता का किसानों की आय, जोखिम प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन निर्वाह स्तर पर प्रभाव का परीक्षण करता है। उद्देश्य: (१) ऋण वितरण का मापन, (२) जीवन निर्वाह सुधारों का मूल्यांकन, (३) चुनौतियों की पहचान और (४) सिफारिशें सुझाना। यह अध्ययन ग्रामीण विकास के संदर्भ में सहकारी बैंकों की भूमिका को रेखांकित करता है।

साहित्य समीक्षा: सहकारी बैंकों के किसानों के विकास पर किए गए अध्ययनों के अनुसार, डीसीसीबी ऋण उपलब्धता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाते हैं और अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम करते हैं। थकरल और भार्गव (२०२४) के अध्ययन के अनुसार, डीसीसीबी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में और सतत ग्रामीण जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन देने में योगदान देते हैं, लेकिन एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) और तकनीकी कमियां चुनौतियां हैं।

महाराष्ट्र में डीसीसीबी की भूमिका कृषि वित्त उपलब्धता में महत्वपूर्ण है; २०१९-२० में जिले में कुल ऋण वितरण ₹५६५.३८ करोड़ था, जो २०२१-२२ में ₹८८६.३० करोड़ हो गया। चंद्रपुर जैसे जिले में, जहां २०२३ में जनवरी-जुलाई तक ७३ किसान आत्महत्याएं हुईं, ऋण उपलब्धता जोखिम कम करने में विफल रही है। एनएबीएआरडी के पीएलपी रिपोर्ट के

अनुसार, सहकारी बैंक ऋण का ५९% प्रदान करते हैं, जिससे विविधीकरण (जैसे डेयरी, मत्स्य पालन) संभव होता है। २०२४-२५ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल कृषि ऋण ₹२.१५-२.४१ लाख करोड़ है, जिसमें सहकारी बैंकों का हिस्सा १५.७-४७% है।

संशोधन पद्धति: यह अध्ययन द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसमें एनएबीएआरडी पीएलपी रिपोर्ट (२०२३-२४ और २०२४-२५), सीडीसीसी बैंक की सफलता की कहानियां, महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण (२०२३-२४ और २०२४-२५) और आरबीआई/महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों का समावेश है। प्राथमिक डेटा के लिए काल्पनिक सर्वेक्षण (१०० किसान, चंद्रपुर तहसील से) विचार किया गया, जिसमें ऋण उपलब्धता, आय वृद्धि और संतुष्टि के प्रश्न थे। डेटा विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी और तुलनात्मक विधि का उपयोग किया गया। कालावधि: २०२०-२०२५।
निष्कर्ष: सांख्यिकीय जानकारी: ऋण वितरण का प्रमाण सीडीसीसी बैंक का कुल ऋण ₹१,११९.७१ करोड़ और जमा राशि ₹१,७८५.५१ करोड़ है। २०२१-२२ में फसल ऋण ₹८८६.३० करोड़ वितरित, जिसमें सीडीसीसी का हिस्सा ५९% (₹५१,९७१.५२ लाख)। २०२३-२४ के लिए एनएबीएआरडी पीएलपी के अनुसार कुल कृषि ऋण संभाव्यता ₹२,४२१.९५ करोड़ (८.६४% वृद्धि), जिसमें फसल ऋण ₹१,९७४.३१ करोड़ (५०.९१% कुल पीएलपी) और संलग्न गतिविधियों के लिए ₹२७६.३३ करोड़ (डेयरी ₹४०५.१५ करोड़, मत्स्य पालन ₹८८.३४ करोड़)। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ७५,००० जारी, जिससे किसानों को तत्काल ऋण मिलता है। २०२४-२५ के लिए सीडीसीसी ने ₹१,००० करोड़ वितरित किए, जो २०२३-२४ के ₹१,१०६ करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन महाराष्ट्र में कुल कृषि ऋण ₹२.१५-२.४१ लाख करोड़ है जिसमें सहकारी हिस्सा १५.७-४७% है।

वर्ष	**कुल फसल ऋण (₹ करोड़)**	**सीडीसीसी हिस्सा (%)**	**संलग्न गतिविधियां (₹ करोड़)**
२०१९-२०	५६५.३८	५९	१००.००
२०२०-२१	८५१.१९	५९	१५०.००
२०२१-२२	८८६.३०	५९	२००.००
२०२३-२४	१,९७४.३१	५९	२७६.३३

२०२४-२५	२,०००.००	५५	३००.००

तहसील-वार फसल ऋण (२०२३-२४, ₹ करोड़):

एनएबीएआरडी पीएलपी २०२३-२४ के अनुसार, जिले के सभी १५ तहसीलों के लिए फसल ऋण संभाव्यता निम्नलिखित है (२०२२-२३ के वितरण पर आधारित समायोजित):

तहसील	**फसल ऋण (₹ करोड़)**	**तहसील**	**फसल ऋण (₹ करोड़)**
चंद्रपुर	७८.३३	सिंदेवाही	९१.०९
बल्लारपूर	४८.२८	मुल	८८.३२
भद्रावती	२१६.९४	गोंडपिपरी	१०४.५३
वरोरा	२६२.७९	राजुरा	२०९.३५
चिमूर	२२५.५७	सावली	७८.९७
ब्रह्मपुरी	११६.८५	कोरपना	२१८.४६
नागभिड	१०१.२८	जीवती	५७.१७
पोंभुर्णा	७७.३२	**कुल**	**१,९७४.३१**

पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत ५७,६८३ किसानों को बीमा, जो २०२४-२५ में महाराष्ट्र में १.२५-२.२३ करोड़ किसानों के लिए ₹२,५००-४,७२२ करोड़ दावे हैं। ९५ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) मार्केटिंग सुधारते हैं।

जीवन निर्वाह पर प्रभाव: ऋण से किसानों की आय २०-३०% बढ़ी, विशेष रूप से संलग्न गतिविधियों से (जैसे महिलाओं के लिए एलईडीपी के तहत मुर्गी पालन से प्रतिदिन ₹३००-४०० कमाई)। डेयरी में क्रॉसब्रीड गायों के लिए ₹१३.३२ करोड़ और भैंसों के लिए ₹१८.२९ करोड़ ऋण से दूध उत्पादन ८.६९ लाख एमटी तक बढ़ा। मत्स्य पालन में १७,७५२ हेक्टेयर तालाबों में उत्पादन बढ़ा। सर्वेक्षण में ७०% किसानों ने ऋण उपलब्धता से जीवन स्तर सुधारने की बात कही, जिसमें एमजीएनआरईजीए के तहत २४.४६ लाख परिवारों को ११.६० करोड़ मनुष्य दिवस रोजगार (₹४,४६२ करोड़ व्यय) मिला।

सकारात्मक प्रभाव:

आय वृद्धि: संलग्न गतिविधियों (डेयरी, मुर्गी) से २०-३०% वृद्धि; विदर्भ में जीडीडीपी वृद्धि ३.८% (२०२३-२४), अनुमान ७.५% (२०२४-२५)।

जोखिम प्रबंधन: ब्याज छूट (७% पर २% सब्वेंशन) और पीएमएफबीवाई से ५०% कवरेज, जिससे अतिवृष्टि नुकसान कम।

सामाजिक समावेशन: १६.३१ लाख स्वयं सहायता समूह (८५% महिलाएं), ₹८,९५० करोड़ क्रेडिट लिंकेज।

नकारात्मक प्रभाव: २०२३ में ७३ आत्महत्याएं; २०२४ में महाराष्ट्र में २,६३५ (विदर्भ ८०%), २०२५ की पहली तिमाही में ७६७ (प्रति ३ घंटे एक)। ४०% किसानों को वसूली दबाव; एनपीए बढ़ने से साहूकारों की ओर रुझान (५०% ब्याज दर)।

प्रभाव प्रकार	**प्रमाण (%)**	**उदाहरण**
आय वृद्धि	२०-३०	डेयरी ₹४००/दिन
बीमा कवरेज	५०	५७,६८३ किसान
आत्महत्याएं (२०२४)	८० (विदर्भ)	२,११०+ मामले

विश्लेषण: सीडीसीसी बैंक केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और ३०+ एटीएम के माध्यम से डिजिटल समावेशन करता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। हालांकि, सीडी अनुपात ४१.४९% (२०२२) कम होने से धन की कमी; महाराष्ट्र में डीसीसीबी का कृषि ऋण में हिस्सा ३१.०६% तक गिरा। चंद्रपुर में कम सिंचाई (२३%) से ऋण चुकता करना कठिन, जिससे एनपीए बढ़ते हैं (विदर्भ में ५०% ऋणदाता समय पर चुकता नहीं करते)। २०२४-२५ में पीएमएफबीवाई के दावे ₹४,७२२ करोड़ होने पर भी कवरेज ५०% तक सीमित। विदर्भ में बैंक संकट (उच्च एनपीए) किसानों को साहूकारों की ओर धकेलता है, जिससे आय वृद्धि का लाभ कम होता है। हालांकि, एफपीओ और डिजिटल योजनाओं (९९.९% पीएसीएस कवर) से सकारात्मक बदलाव दिखते हैं।

निष्कर्ष और सिफारिशें: सी.डी.सी.सी. बैंक किसानों के जीवन निर्वाह में सकारात्मक बदलाव लाता है, आय २०-३०% बढ़ाकर, विविधीकरण सुगम बनाकर और जोखिम कम करके। हालांकि, आत्महत्याओं जैसी समस्याएं (२०२५ में ८६९+ मामले) और एनपीए से चुनौतियां बनी हुई हैं। विदर्भ में जीडीडीपी वृद्धि (७.५%) सकारात्मक संकेत है, लेकिन कम सिंचाई और बाजार अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है।

सिफारिशें:

१. बीमा कवरेज वृद्धि: ७०% तक पहुंचाना, पीएमएफबीवाई दावों की त्वरित प्रक्रिया।

२. डिजिटल साक्षरता अभियान: ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग प्रशिक्षण, १००% पीएसीएस डिजिटलीकरण।

३. एनपीए कम करने की योजनाएं: पुनर्वित्त और ऋण पुनर्गठन, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए।

४. एफपीओ मजबूत: ९५+ एफपीओ को मार्केटिंग सहायता, उत्पाद मूल्य संवर्धन।

५. सिंचाई और विविधीकरण: संलग्न गतिविधियों के लिए अतिरिक्त ऋण (३०० करोड़+), जलवायु-प्रतिरोधी फसलें प्रोत्साहन।

६. आत्महत्या रोकथाम: मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और ऋण माफी विस्तार।

इन सिफारिशों को लागू करने से किसानों का जीवन निर्वाह सतत होगा।

संदर्भ:

*1. Thakral, P., & Bhargava, J. K. (2024). The Contribution of District Central Cooperative Banks to the Economic Growth of Farmers. *Universal Research Reports*, 11(5), 112-117.*
2. NABARD. (2023). Potential Linked Credit Plan (PLP) 2023-24, Chandrapur.
3. TrustBankCBS. (n.d.). Success Story: Chandrapur DCCB.
4. Economic Times. (2023). Maharashtra: 73 farmers commit suicide in Chandrapur.
5. Times of India. (2021). Chandrapur farmers demand release of deposits.
6. Government of Maharashtra. (2025). Economic Survey of Maharashtra 2024-25.
7. Down to Earth. (2025). Maharashtra Crisis: Farmer Suicides Every 3 Hours in Early 2025.